ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-7* October-2020
Anthology : The Research

# भारत आसियान संबंध चुनौतियां एवं अवसर
# India ASEAN Relations Challenges and Opportunities

Paper Submission: 15/10/2020, Date of Acceptance: 26/10/2020, Date of Publication: 27/10/2020

**विजय कुमार शर्मा**
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

**सारांश**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्त्व में बनी नई सरकार ने देश की आर्थिक और विदेश नीति की संभावनाओं को एक नई गति देने का काम किया है, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्त्व वाली पिछली सरकार के तहत बाकी रह गया था। भारत आज चीन ओर जापान जैसी पूर्वी एशियाई ताकतों और अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ संपर्कों की एक नई गहराई का प्रदर्शन कर रहा है। मोदी प्रशासन धीरे–धीरे लेकिन स्थिर तौर पर देश की अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में विकास और नौकरियों के उत्पादन को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। आज के दौर में यूरोपियन हिस्से का केन्द्रीयकरण चीन पर है यह यूरोपिय देषों के लिए मौका है कि शांति, बहुलता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एषिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थों से संबंधों के बारे में भी सोचें।

The new government led by Prime Minister Narendra Modi has given a new impetus to the country's economic and foreign policy prospects, which remained under the previous government led by the Congress Party. India is today demonstrating a new depth of contacts with East Asian forces like China and Japan and with its South Asian neighbors. The Modi administration is slowly but steadily pursuing the development and production of jobs in the direction of improvement of the country's economy. In today's era, the centralization of the European part is on China. It is an opportunity for European countries to think about relations with other major economies of Asia to promote peace, plurality and prosperity.

**मुख्य शब्द :** आतंकवाद, आसियान, चुनौतियां ।
Terrorism, ASEAN, Challenges.

**प्रस्तावना**

भारत–आसियान के 50 वर्षो के दौरान आसियान विकासशील देशों में क्षेत्रीय सहयोग के सबसे सफल प्रयोगों में से एक रूप में उभरकर सामने आया है। प्रयास और जीत की अपनी अनेक नीतियों के जरिये आसियान दक्षिण–पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय पहचान की भावना विकसित करने में एक बहुत रचनात्मक और प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अपने अस्तित्व के इस आदी शताब्दी के दौरान आसियान ने वियतनाम का कम्बोडिया पर आक्रमण एशियाई वितीय संकट पारगमन और शरणार्थियो का अन्तर्प्रवाह नशीली दवाओं की तस्करी और अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पूर्वी तिमोर संकट म्यांमार का सैन्य दमन जैसी बड़ी समस्याओं, इण्डोनेशिया के वनों मे लगती आग, छोटे–छोटे संघर्ष, आतंकवाद तथा आईएसआईएस हमले, दक्षिण चीन सागर विवाद आदि जैसी अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं ने न केवल इस क्षेत्र और देशो के अस्तित्व के लिए, बल्कि समग्र रूप क्षेत्रिय व्यवस्था के भविष्य के लिए भी खतरे खडे कर दिये थे।

इसके अलावा 1990 के दशक के मध्य में थाईलैण्ड के तहत, म्यांमार के सैन्य दमन, कम्बोडिया का सैन्य विद्रोह, मलेशियाई उप प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इत्यादि की बर्खास्तगी जैसे सभी मामलो को लेकर पडोसी देशो के विभिन्न राजनितिक नेताओ की तरफ से सरकार की नीतियों पर आलोचनाएँ हुई है, और गैर–हस्तक्षेप और गैर–टकराव के आसियान के सिद्धांतो को लेकर एक बडा प्रश्न चिन्ह खडा कर दिया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र भी घरेलू समस्याओं को बडां पैमाने पर गवाह बना है। जिसके स्पष्ट रूप से अन्तर्राष्ट्रीय आयाम है। और पडोसी देशो के साथ–साथ पूरे क्षेत्र पर प्रतिकुल प्रभाव डाल रहा है। इसलिए सभी मुददो ने आसियान के सामान्य कार्यकलापों को कई मायनों में बाधित कर दिया और आसियान के सदस्यों के बीच फरवरी

1976 में हस्ताक्षरित मित्रता एवं सहयोग संधि के आधार पर गैर हस्तक्षेप और गैर – टकराव के आसियान के सिद्धांतो को लेकर एक बड़ा प्रष्न चिन्ह उठा दिया। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं ने 1990 के मध्य में इसके मुख्य सिद्धांत गैर हस्तक्षेप के विशेष संदर्भ के साथ आसियान के संचालन और कामकाज पर समय–समय पर राजनीतिक और संरचनात्मक बहस छेड दी थी। हालांकि लम्बे समय तक चलती उस बहस के बाद अन्ततः सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति के आधार पर अपने कार्यकलापों के आवश्यक जोड़ने वाले बंधन के रूप में अहस्तक्षेप के सिद्धांत को अपना लिया बदलती हुई परिस्थतियों को ध्यान में रखने के लिए आखिर समायोजन वाला मुद्ददा क्या है। कुल मिलाकर अहस्तक्षेप पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े एक अमूर्त नैतिक चिंता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि किसी ऐसे व्यावहारिक आवश्यकता के मुददो के रूप में देखा जाना चाहिए। जिसके बिना आसियान नही रह सकता है और वास्तविक दुनिया में होते परिर्वतनों और चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता है।[1]

**अध्ययन का उद्देश्य**

1. राजनैतिक परिदृश्य एवं विदेशनीतियों का आकलन भारत–आसियान संबंधो के संदर्भ में विश्लेषित करना।
2. एन.डी.ए. शासनकाल में भारत की विदेशनीति में निरन्तरता एवं परिवर्तन का अध्ययन।
3. भारत–आसियान संबंधो को वर्तमान परिदृश्य के अनुसार विश्लेषित करना।
4. भारत–आसियान नवीन समझौतो का भविष्य की रणनीति के रूप में अध्ययन करना।

**विषयवस्तु**

आसियान के सदस्यों के लिए जो कुछ सबसे ज्यादा जरूरी दिख रहा है वह उनकी अनेक आन्तरिक समस्यायों से है। जिनके क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयाम है। और कभी–कभी दक्षिण–पूर्वी एशिया के देशो के बीच गंभीर तनाव और विभाजित विचार पैदा करती है हालांकि अधिकांश मामले में समस्या की गहराई को महसूस करते हुए आसियान के सदस्य स्पष्ट रूप से समझते है कि यह बहुत ज्यादा समय तक ये समस्यायें प्रभावित देशों तक सीमित नहीं रहनें वाली है। और यहि कारण है। कि ज्यादातर सदस्य इसे लेकर एक समन्वित और ठोस जवाब की मांग करते है। इसके परिणामस्वरूप आसियान के सदस्यों ने समस्याओं को हल करने और संकट को रोकने को लेकर अपने क्षेत्रीय संसाधनों को जुटाने के लिए मिलकर काम करने की कोशिश की है। आसियान के सदस्यों का समग्र नजरिया पूरी तरह से वार्त्ता, परामर्श, सहयोग, संलग्नता और पारस्परिक सम्पर्क पर आधारित है। इसे रिष्तो को अधिक 'लचीला' और बातचीत को आगे बढ़ाना पसंद है। यही कारण है कि सम्पर्क और बातचीत दोनों में ही निरंतरता रहती है। यह जो कुछ वांछित है और जो कुछ संभव है के बीच आदर्श और व्यावहारिक के बीच, वांछित उद्देश्यों और उपलब्ध साधनों के बीच और अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी तथा राष्ट्रीय सम्प्रभुता के बीच संतुलन बनाने का भी प्रयास चल रहा है।[2] यह अहस्तक्षेप के सिद्धान्त से अलग हुए बिना, क्षेत्रीय आम सहमति से अपनी कई समस्याओं से निपटने की कोशिश करता है। आसियान के ज्यादातर सदस्यों का मानना है कि ये सिद्धांत संगठन की प्रकृति में ही बहुत हद तक निहित है और इन सिद्वांतों ने आसियान की सफलता में योगदान दिया है और भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। यह वास्तविकता है कि अपने पांच दशकों के अस्तिव के दौरान कुल मिलाकर आसियान के अर्थशास्त्र ने 1967 से 2016 की लम्बी अवधि का रास्ता तय किया है। इसके अलावा 2003 में आसियान के सदस्यों ने असियान आर्थिक समुदाय (एईसी) की आकांक्षाओं को अपनाया था, जिसमें निम्न व्यापार तथा निवेश बाधाओं सहित आर्थिक सहयोग के उपायों सुसंगत निवेश एवं विनिमय और उत्पादन के वैष्विक मूल्य श्रृंखला में इस क्षेत्र की स्थापित करने के तरीके पर रोशनी डाली गयी थी। इसका उदेश्य एक 'एकल बाजार और उत्पादन आधार बनाने और 1990 के दषक में आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र के तहत टैरिफ उदारीकरण के माध्यम से मदद की तुलना मे अधिक लाभ कल्याण पैदा करना है। इसके बावजूद आसियान अपने हित धारको के लिए एक एकल बाजार उपलब्ध कराने से अभी भी दूर है। यह इसलिए है, क्योकि टैरिफ बाधायें वैसी ही बनी हुई है। यह क्षेत्र बुनियादी ढांचे की कमी से भी ग्रस्त है। कारक टैरिफ उदारीकरण के पूर्ण लाभ पाने से रोकते है इसके अलावा यह क्षेत्र अपने सदस्य देशों के बीच के विकास की विषमता वाली कठिनाइयों का भी अनुभव करता रहा है। इस प्रकार कहा जाता है कि अपने सदस्य देशों के बीच के निर्धारित लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण प्रतिषत प्राप्त करने के बावजूद आसियान ने अभी तक अपने एकल बाजार उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है।[3]

आसियान द्वारा अख्तियार किया गया तरीका एक ऐसी बानगी है। जो अपने सभी छोटे–बड़े सदस्यों को आम सहमति की गारंटी देती है कि निर्णय लेने में सभी शामिल है। आसियान सदस्यों की व्यापक विविधता के बावजूद उन्हें क्षेत्रीय सहयोग के रास्ते पर एकजुट करने और रखने की आवश्यकता है। मौजूदा लुक ईस्ट के चरण में सुरक्षाश्का पहलु निश्चित तोर पर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अमेरिका, जापान या दक्षिण पूर्वी एशिया नीति निर्माता इस बात से सहमत लगते है कि जब तक रणनीतिक तौर पर रिष्ते परिभाषित नही होते है। द्विपक्षीय रिश्तों को बहुत दिनों तक नही चलाया जा सकता है। इस तरह से कोई भी सुरक्षा की वार्ता और रक्षा समझौतों की आशा कर सकता है। और लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए अभी ये प्राथमिकता के विषय बने रहेगे। भारत का हिन्द महासागर में सबसे बडी नौसेनिक मौजूदगी को चुनौति दे पाना बहुत ही मुश्किल है और अडमान पर नई कमांड की उपस्थिति भारत के पूर्वी हिस्से पर जोर का दूसरा करती है। जहॉ तक आर्थिक संबंधों सम्पर्को की बात है तो 1990 के दषक के मुकाबले निवेश का माहौल बेहतर है।[4]

आँकडो की जहाँ बात है तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत बेहतर हो रहा है। भारत इस मामले में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। चीन और जापान से उलट उस पर आक्रमण और दखल का कोई बोझ नही है। भारत अपने

दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशो के साथ किसी भी समुद्री सीमा से जुडे विवाद में नही फंसा हुआ है। वास्तव में भारत दक्षिण–पूर्वी एशिया में विशिष्ट तरीके से एक संतुलनकारी भूमिका में खडा़ हो गया है, क्योंकि यह क्षेत्र किसी महान शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में नही आता है। अपने साफ–सुथरे इतिहास के रिकॉर्ड के चलते भारत रणनीतिक तौर पर ऊपर हो सकता है, क्योंकि यह किसी भौगोलिक विवाद में शामिल नहीं है और जपान, अमेरिका वियतनाम और इण्डानेशिया के साथ बहुत सारे साझें हितों की साझेदारी करता है। लेकिन चीन को रोक पाना मुश्किल है और इस तरह की किसी मुहिम का भारत कतई हिस्सा नहीं बनाना चाहेगा। इसके साथ ही यह चीन के आर्थिक आकर्षण को देखते हुए भी उससे साम्य नहीं खाता है। भारत खुद चीनकी आर्थिक प्रगति से लाभ हासिल करना चाहता है।[5]

इससे भी आगे भारत का पूर्वी एशिया में हित बहु–आयामी है। जिसमें यह सुरक्षा की चुनौतियों के दायरे अमेरिका से नजदीकी संबंध है। जिनके साथ इसकी किसी भी तरह की द्विपक्षीय समस्या नहीं रही है और शांति और स्थायित्व के लिहाज से दोनों एक दूसरे के लिए मददगार ही रहे है और एक स्थाई, बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा मे काम कर रहे है। दूसरे शब्दों में कई ऐसे दूसरे भी कारण है जो भारत की नीति के केवल चीन वहीं बल्कि दक्षिण–पूर्वी एशिया की तरफ ले जाने के लिए जिम्मेदार है।[6]

एक देश के विकास को उच्चत्तम स्तर तक पहुँचाने के लिए घरेलू प्राथमिकताओं को अन्तर्राष्ट्रीय दायरे तक खींच ले जाना सबसे बेहतर विकल्प होता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने कुछ पूर्वी एशियाई देशों के साथ पवित्र संबंधों को फिर से जीवित कर दिया और बाजार आधारित विकास के मॉडल के बाद आपसी लाभ के लिए उसे विकसित करने की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ा दिया। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत का संबंध भूमंडलीकरण से पहले प्रारंभ हो गया था जबकि चीन के साथ 1990 के दशक में आगे बढ़ा। वैश्विक बाजार और क्षेत्रीय आर्थिक शक्तियों और समूहों से खासकर आसियान से एकता बद्धता ने एक नये विचार रणनीति के शामिल होने की वजह बना क्योंकि आर्थिक संबंध इस दौर में दूसरे संबंधों पर भारी पड़ रहे थे।[7]

दो दषकों के भीतर भारत ने अपनी क्षमताओं को बढ़ा लिया और इसके साथ ही एशिया में एक प्रमुख शक्ति के तौर पर उभरा। एक अगुवा भूमिका को बनाए रखने और उसे मजबूत करने से घरेलू समृद्धि को बनाए रखने और उसे मजबूत करने से घरेलू समृद्धि को आगे बढ़ाने का मौका मिला इसके साथ ही एशिया की दो बड़ी शक्तियों चीन और जापान के साथ सामरिक और आर्थिक साझेदारी के प्रबंधन के विवेक को भी समझने में मदद मिली। एक्ट ईस्ट नीति, ने हिन्द महासागर और पैसिफिक देशों के साथ उसके संबंधों को विस्तारित कर दिया है लेकिन कई कारणों से यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। नीचे दी गई बातचीत पूर्वी एशिया की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की भारत का पूरी तरह से तैयार कुटनीतिक गणित और जटिल विश्व व्यवस्था में शामिल द्विपक्षीय संबंधों की उलझनों की चुनौतियों को बढ़ाने का काम करता है।[8]

दक्षिण–पूर्वी एशिया की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ने की भारत की रणनीतिक पहल एक तालमेल के तौर पर सामने आयीहै जो आने वाले समय में बहुत उत्पादक होने जा रही है। एशिया में भारत के बढ़ते कद के अनुरूप रही है लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में बदलाव की नीति एक्ट ईस्ट आगे बढेगी और आने वाले दिनों में इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा मुहैया कराने वाली होगी। टिकाऊ स्वास्थ्यप्रद अर्थव्यवस्था और रणनीतिक माहौल के जरिये जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ विशिष्ट सामरिक साझेदारी हमारी क्षेत्रीय कुटनीति में इसकी ताकत को प्रमाणित करता है। बगैर सैन्य गठबंधन के इंडो–पैसिफिक एशियाई क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत सहयोग सैन्य ढांचे के लिए रणनीतिक जगह को विस्तारित करने में सफल रहा है।[9]

लेकिन भारत की अनिश्चित अर्थव्यवस्था की स्थिति और क्षेत्रीय प्रतियोगी माहौल के मद्देनजर काम बहुत चुनौतिपूर्ण है। एशिया में एक नेतृत्त्वकारी भूमिका निभाने की दिशा में भारत को ढेर सारे देशों से सहयोग को विस्तारित करने की जरूरत है। जिससे यह अपनी अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमताओं को विस्तारित कर सके। जहाँ तक इसके नजरिये की बात रही तो वह सजग, बदलावों पर प्रतिक्रियात्मक और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खोजी रणनीति वाला होना चाहिए। लेकिन भारत का विकसित दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार बहुत निराशाजनक रहा है। उनमें बहुत क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मुकाबला कर रहे है, लेकिन मुख्य चुनौती चीन से है।[10]

भारत की लुक ईस्ट नीति को मौजूदा चुनौति उस समय सामने आती है जब चीन के उभार से पूर्वी एशिया में सामरिक संतुलन बिगड़ता है और इस बात की अवधारणा बनती है कि अमेरिका की परम्परागत स्थिरता मुहैया कराने की भूमिका सीमित हो चुकी है। दक्षिणी चीनी समुद्र में चीन और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बीच परम्परागत विवाद को फिर से पैदा होना साथ ही पूर्वी चीनी समुद्र में चीन और जापान के बीच और अब दक्षिण कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया का हमलावर रूख यह सब दिखाता है कि क्षेत्रीय सामरिक संतुलन बिगड़ गया है। दूसरी तरफ भौगोलिक मसलों पर चीनी दावेदारी भारत को अपने विस्तार का एक नया मौका मुहैया कराता है जिसमें वह चीन के इर्द–गिर्द वाले देशों के साथ संबंधों को गहरा कर पूरा कर सकता है।[11]

मोदी के तहत् भारत ने विदेश नीति के लिए एक बहु आयामी नजरिये को अपनाया है जिसमें न केवल एक पड़ोसीपन की रणनीति है, बल्कि व्यापार और निवेष को बढ़ाने के लिए दूर के पूर्वी एशियाई देशों तक पहुँचाने का भी है। इस महान् रणनीति के लक्ष्य को और बढ़ाते हुए घरेलू आर्थिक विकास को गति देने की जरूरत है। जिससे भारत अपने लोगों के कल्याण और उसकी सुरक्षा दोनों को बेहतर किया जा सके। आसियान चुनौतियों को निम्न प्रकार देखा जा सकता है –

1. एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन।
2. आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी अधिक है।
3. सिंगापुर में प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे अधिक है, जबकि कम्बोडिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी कम है। कम विकसित देषों को क्षेत्रीय योजनाओं, प्रतिबद्वताओं को लागू करने के लिये संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है।
4. दक्षिण चीन सागर में दरार पैदा करने वाला मुख्य मुद्दा है।
5. आसियान को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दो पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए रोहिंग्याओं के खिलाफ म्यांमार में दरार।
6. सहमति को लागू करने के लिए कोई केन्द्रीय तंत्र नहीं।
7. आम सहमति पर अत्यधिक बल मुख्य दोष है। कठिन समस्याओं का सामना करने के बजाय टाल दिया जाता है।
8. असक्षम विवाद–निपटान तंत्र चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक।

**निष्कर्ष**

हालांकि इस परिणाम को नकारात्मक रणनीतिक परियोजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके सदस्य देशों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृखंला को नियंत्रित करने वाले और इससे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मामलों में इसकी ताकत को सौपने वाले किसी उपाय के रूप में इसकी व्याख्या की जा सकती है। अपने कई लक्षित क्षेत्रों की उपलब्धि की कमी की आलोचना किये जाने के बावजूद यह समकालीन वैश्विक राजनीतिक मे एक प्रमुख क्षेत्रीय और विशिष्ट रूप से सफल क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभरा है। पिछले पॉच दशकों के अपने लम्बे इतिहास के दौरान, आसियान की सहमति से लिए गये निर्णय वाले मॉडल की सराहना और निंदा दोनों ही उचित रूप से की गई।

**संदर्भ ग्रंथ सूची**

1. *ठाकुर रमेश 1992, "इण्डिया ऑफ्टर नॅन–अलाईगमेन्ट, फोरेन अफेयर्स 71 (2), पृ. 162–82.*
2. *त्रिपाठी सुधांशु 2004, "इण्डियाज फोरेन पोलिसी, ट्रांसफोरमेशन एण्ड चैलेंजेज, वर्ल्ड फोकस, न्यू देहली अक्टूबर, नवम्बर दिसम्बर, वोल्यूम 25 नं. 298–300 पृ. 7–9*
3. *अमीतव आचार्य, "इण्डियाज लुॅक ईस्ट पोलिसी, इन डेविड मेलोन, सी. राजा मोहन, द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इण्डियन फोरेन पोलिसी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सीटी प्रेस, पृ–457*
4. *डेविड एम. मेलेनो (2011), डज द एलिफेन्ट डोन्स? कंटेमपरेरी इण्डियन फोरेन पोलिसी, ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क पृ. 202*
5. *प्रकाश नन्दा (2003) रिडिसकवरिंग एशिया, इवोल्यूशन ऑफ इण्डियाज लुक ईस्ट पोलिसी, लेन्सर पब्लिकेशन पृ. 274*
6. *अनिल शशि (2014) " लुक ईस्ट हैज बीकम एक्ट ईस्ट पोलिसी, द इण्डियन एक्सप्रेस $13th$ नवम्बर*
7. *मुचकुन्द दुबे (2013) इण्डियाज फोरेन पोलिसी, पियर्सन दिल्ली, पृ–263*
8. *मोहन– "ए न्यू वे टूएक्ट ईस्ट (2015)*
9. *सी. राजा मोहन – मोदीज वार्ड हारपर कोलिन्स पब्लिशर्स इण्डिया, नोएड़ा पृ – 147*
10. *संजय बारू (2015), इण्डिया–जापान चार्ट एशियाज पीसफुल राइज, द हिन्दू 15 दिसम्बर पृ–10*
11. *अरूण विश्वनाथन एण्ड एस. चन्द्रशेखर, "व्हाई इण्डियाज सुड बी वरिड़ "डेकन हैराल्ड, 5 फरवरी 2016*